STATEMENT *RE* ARRESTS IN NEW DELHI ON 12TH DECEMBER, 1967 FOR DEFYING PROHIBITORY ORDERS

THE MINISTER OF STATE IN THE MINISTRY OF HOME AFFAIRS (SHRI VIDYA CHARAN SHUKLA) : Madam, yesterday, on the 12th instant, Shri Phabhu Narain Singh, Shri Ram Swaroop Verma, Shri Bachan Ram and nine others were arrested at about 2.15 P.M. while taking out a procession on the Talkatora Road in defiance of the prohibitary orders under section 144 Cr. P.C. duly promulgated by the District Magistrate, Delhi. They are being prosecuted before a Court of competent jurisdiction for committing an offence under section 188 I.P.C. They were produced before the Court at about 4.45 P.M. yesterday and have been remanded to judicial custody, and the matter in *sub judice*. The case is expected to come up for hearing today.

श्री राजनारायण (उत्तर प्रदेश) : ो माननीय मंत्री जी ने बयान दिया है इस संबंध में कल हमने एक लिखित पत्र चेयर के पास भेजा था और एक बड़े घर मंत्री साहब को भी, जो यहां थे, लिख कर भेजा था ।

यह मामला सबजुडिस नहीं है । पहले तो यह साफ हो जाना चाहिये कि यह सबजुडिस नही है । सवाल यह है कि दफा 144 किस काम को रोकने के लिये लगाया जाता है । मैं आपके द्वारा एक नहीं अनेक हाईकोर्ट और सुप्रीम कोर्ट की व्यवस्था दे सकता हूं और उसी व्यवस्था की तह मे कई बार मै मुक्त भी हुआ । केवल दफा 144 को तोड देने मे अपराध नही बनता । एक बात साफ है कि श्री प्रभुनारायण सिह और श्री राम स्वरूप वर्मा, क्रमश: श्रम मंत्री और वित्त मत्री अपने नौ-दस साथियों के साथ इस अंग्रेजी लादे जाने वाले विधेयक के विरोध मे कुछ कहते हुए आ रहे थे, नारे भी लगा रहे थे । उनका कहना था : 'अंग्रेजी में काम न होगा, फिर से मुल्क गुलाम न होगा; हम किसान और मजदूर, कर देंगे अंग्रेजी दूर. . .'

श्री नेकी राम (हरियाणा) : इसका क्या मतलब होगा ?

श्री राजनारायण : मतलब नहीं समझते हो तो कल समझोगे । मुझे तो हैरत है कि इस 144 के आदेश का अनौचित्य स्वत: सिद्ध हो गया कि प्रभुनारायण जी और रामस्वरूप वर्मा जी की गिरफ्तारी के बाद कोई घटना नहीं घटी, कोई वहां पर उत्तेजना नही हुई, कोई वहां आग नही लगी, कोई बलवा नही हुआ, किसी पर ईटें पत्थर नही चले । यह बिल्कुल सिद्ध हो गया कि दिल्ली में 144 धारा का लगाया जाना ही गैरकानूनी था और मै आपके जरिये पुन: निवेदन करूंगा, माननीया, कि यह कोई मामूली मसला नही है । एक रूलिंग मै बता रहा हूं जो हमारे एक मुकदमे में जज ने दिया है : Disobedience of an illegal order cannot amount to an offence. अर्थात् गैरकानूनी आदेश को तोड़ना अपराध नही बनता । दफा 144 कल सिद्ध हो चुका कि गैर कानूनी है । मै रात को, माननीया, घर मे बैठा था, दस बजे रात रेडियो बोला कि 12 बजे रात से अब सम्पूर्ण दिल्ली मे 144 लग जायेगा और दिल्ली यूनिवर्सिटी अनिश्चित समय के लिये बंद कर दी गई है । यह देखा जाय कि केन्द्र की सरकार स्वत: इस गलत ढंग से ाषा विधेयक ो लेकर इस मुल्क के वातावरण को क्षुब्ध कर रही है । तो मै आपके जरिये निवेदन करूगा कि यह सदन इस सरकार को आदेश करे कि तत्काल 144 की दफा हटाई जाय, 144 का जो गैर-कानूनी दफा है उसको तोड़ने में जो लोग गिरफ्तार हुए है वे फौरन रिहा किये जायं । सबसे आश्चर्यजनक चीज है, मै 8 बजे जेल गया था वहां से सीधे यही चैम्बर मे आया ।

[श्री राजनारायण]

श्री प्रभुनारायण और रामस्वरूप वर्मा मन्त्री है, बाकी विधायक है और जो गिरफ्तार हुए है सब एम० ए० है और मौजूदा मन्त्रियो को पढाने की क्षमता रखते है, उनको 'बी' क्लास दिया गया है। जेल मे तीन क्लास है, ए, बी और सी। 'ए' क्लास किसके लिये है, क्या श्रीमती इन्दिरा नेहरू गाधी के बच्चो के लिये या अशोक चौह्वाण के लिये है? मै आश्चर्यचकित हू जब अखबार मे मैने पढा उन लोगो को 'बी' क्लास मे रखा गया है। उत्तर प्रदेश मे केवल दो क्लास है, एक सुपीरियर, एक आर्डिनरी। मगर दिल्ली मे तीन क्लास है-- हम भी यहा तीन, चार बार जेल काट चुके है।

तो क्या सरकार अब भी कृपा करेगी और बताएगी कि वह मजिस्टर और वह पुलिस आफिसर जिन्होने कि कल ढाई घटे तक उन मन्त्रियो को थाने मे और अदालत मे खडा रखा, उनको कोई चेयर नही मिली, यह क्यो हुआ। उन्होने कहा, हम यहा उठा कर बुलाये गये है, मगर हमको खडा रखा गया है, हमको बैठने की कोई सुविधा नही है। मजिस्टर कहता है, हमारे यहा कागजात नही आए। जब मै वहाँ से निकल कर फिर यहा आया, माननीया, तब भार्गव जी यहा थे, मैने कहा चह्वाण साहब से कि यह कर क्या रहे हो, इस ढग से अगर हैरासमेन्ट किया जायेगा, दो-दो ढाई-ढाई घटे तक थाने और अदालत मे खडा किया जायेगा तो यह हैरासमेन्ट है, इस पर रोक लगानी चाहिये। तो मै सरकार से जानना चाहता हू, ऐसी अनियमितताए, इस प्रकार का अपमानजनक व्यवहार क्यो हो रहा है?

श्री विद्या चरण शुक्ल . उपसभापति महोदया, इसमे जहा तक 144 धारा के कानूनी या गैर कानूनी होने का सवाल है, अपने बचाव का पक्ष अभियुक्त लोग अदालत के सामने पेश कर सकते है। मै नही समझता सदन के सामने इन सब बातो पर बहस हो सकती है। जहा तक सवाल है वह बात करते हुए चले आ रहे थे, तो यह सब जानते है कि अखबारो मे इस बात की घोषणा की गई थी कि वह जलूस निकालेगे, धारा 144 को तोडेगे, और वे झडा लेकर नारे लगाते हुए जलूस लेकर आ रहे थे और उन्होने धारा 144 तोडी। इस अपराध मे उन्हे गिरफ्तार किया गया।

जहा तक 'बी' क्लास देने का सवाल है, मै माननीय सदस्य को बतलाना चाहता हू कि उन्हे "ए" क्लास दिया गया है, "बी" क्लास नही दिया गया है और अखबारो मे जो खबर निकली है, वह गलत है।

जहा तक कुर्सी देने का सवाल है, मै यह कहना चाहता हू कि कभी कभी गवाहो को कुर्सी जरूर दी जाती है। अभियुक्तो को अदालत के सामने, कानून के सामने बराबर और एक तरह से माना जाता है, चाहे किसी का दर्जा कुछ भी क्यो न हो और वे अपने जीवन मे चाहे कोई दर्जा क्यो न रखते हो। कानून के सामने सब के साथ समान व्यवहार किया जाता है और इसमे भी कोई अपमान नही किया गया बल्कि कानून के अनुसार उनके साथ व्यवहार किया गया।

श्री चन्द्र शेखर (उत्तर प्रदेश) : महोदया, मै आपके जरिये गृह मन्त्री जी से निवेदन करना चाहूगा कि एक बात की उन्होने सफाई की कि दोनो मन्त्रियो को प्रथम श्रेणी दी गई है, द्वियीय श्रेणी नही दी गई है। यह बात ठीक है। लेकिन जहा तक दोनो मन्त्रियो का कानून तोडने से सबध है, मै इस बात मे कोई औचित्य नही देखता हू कि उन्हे ढाई घटे तक थाने मे खडा रखा गया। मै यह भी नही मानता हू कि शासन मे कोई ऐसा नियम है कि कचहरी के सामने किसीको कुर्सी न दी जाय। मै तो एक

साधारण राजनैतिक कार्यकर्ता रहा हू और मैने दो एक बार इस तरह से नियमो को तोडा और गिरफ्तार किया गया और मेरे जैसे आदमी को भी कुर्सी वहा पर मिली। अग्रेजो के जमाने मे जब पडित जवाहरलाल नेहरू और बडे बडे नेताओ को कुर्सी दी जाती थी और कल किसी मेजिस्ट्रेट ने इन मत्रियो को ढाई घटे तक बैठने के लिए कोई कुर्सी नही दी यह निन्दनीय है। इस प्रकार की प्रवृत्ति को बढावा नही दिया जाना चाहिये।

जहा तक माननीय राजनारायण जी का प्रश्न है उससे मै सहमत नही हू कि दफा 144 तोडना कोई जुर्म नही है। मै कहना चाहता हू कि जो कानून तोडता है उसके ऊपर जुर्म बनता है। महोदया, मै आपके जरिये श्री राजनारायण जी से कहूगा कि उत्तर प्रदेश मे जिस सरकार के वे भागीदार है, उसने उनके ही दो एम० एल० एज० को--श्री हुक्म सिह को आगरा मे और श्री चन्द्र शेखर सिह को बनारस मे, जहा से श्री राजनारायण जी आते है, दफा 144 को तोडने मे गिरफ्तार किया गया है। हमारे राजनारायण जी ने उनकी गिरफ्तारी के सबध मे उत्तर प्रदेश सरकार की भर्त्सना करना अच्छा नही समझा। आज के अखबार मे निकला है कि मध्य प्रदेश के इन्दोर जिले मे, जहा की सरकार मे श्री राजनारायण जी भागीदार है, वहा करफ्यू लगा दिया गया है।

THE DEPUTY CHAIRMAN : Clarifications can be asked. You are not replying to him. You are asking clarification from the Minister.

श्री चन्द्र शेखर मै यह कहना चाहता हू कि जहा अनुशासन तोडा जायगा, कानून तोडा जायगा, वहा कानून अपना काम करता है, चाहे वह मध्य प्रदेश मे हो, चाहे वह उत्तर प्रदेश मे हो, जहा कि श्री राजनारायण जी भागीदार है।

श्री विद्याचरण शुक्ल : सवाल जो पूछे गये है, उनमे एक यह है कि उनको मेजिस्ट्रेट के सामने पेश करने मे ढाई घटे की देरी क्यो की गई। इस सबध मे मै यह कहना चाहता हू कि जब उन्हे गिरफ्तार किया गया तो उसके बाद कुछ डाक्यूमेट तैयार किये जाने थे। अगर डाक्यूमेट तैयार हो जाते तो मेजिस्ट्रेट उसी दिन उनका ट्राइल कर देता। चूकि डाक्यूमेट तैयार करने मे इतना समय लग गया और इसी वजह से उन्हे ढाई घटे तक रोका रखा गया। डाक्यूमेट तैयार करने मे देरी हुई, मै इस बात को मानता हू। लेकिन जितनी होना चाहिये थी, जितनी जल्दी करना था, उतना उन्होने करने का प्रयत्न किया।

श्री सुन्दर सिह भंडारी (राजस्थान) : मै माननीय मत्री जी से एक स्पष्टीकरण यह चाहूगा कि यह जो डाक्यूमेट तैयार करने मे देरी हुई वह इसलिए हुई थी कि अब भी वही पद्धति बनी हुई है कि पहले डाक्यूमेट अग्रेजी मे तैयार किये जाते है और जब कोई उन्हे अग्रेजी मे लेने से इन्कार करता है तब उनको हिन्दी मे अनुवाद करने की व्यवस्था की जाती है और फिर हिन्दी मे दिया जाता है? जब सारे देश-भर मे इस तरह का वातावरण बना हुआ है, इस तरह की घटनाएं हो रही है, तो क्या मत्री महोदय इस घटना को उदाहरणस्वरूप लेकर जहा पर हिन्दी मे काम हो सकता है वहा पर करने की व्यवस्था करेगे? जहा अब भी अग्रेजी मे ही डाक्यूमेट बने हुए है और अग्रेजी मे ही डाक्यूमेट दिये जाने की प्रवृत्ति बनी हुई है, उसको कम करने का आग्रह करेगे? यह तो पहली बात है।

दूसरी बात मै यह कहना चाहता हूं कि जहा तक अदालत मे कुर्सी न देने का सवाल है और जो पद्धति है, मै समझता हू कि उन्होने एक नई परिपाटी की व्याख्या करने की कोशिश की है। पहले भी लोगो

[श्री सुंदर सिंह भंडारी]

को अदालत में कुर्सी दी जाती रही है और आज जान-बूझकर कि वे लोग कांग्रेस पार्टी के नहीं हैं, इसलिए उनको कुर्सी नहीं दी जायेगी। तो मैं आप से निवेदन करूंगा कि आप इस बात की कोशिश न करें कि अदालतों में जो परिपाटी और परम्परा बनी हुई है वह किसी एक पार्टी के लिए नहीं बनी हुई है, यह बात कहकर आप इस बात को टालने की कोशिश मत करिये।

तीसरी चीज़ जो मैं कहना चाहता हूं वह यह है कि पिछले महीनों से ही आपने यहां पर यह नियम जैसा लागू कर दिया है कि जब संसद का अधिवेशन चालू हो, तो चाहे कोई कारण हो या न हो, पहले से ही संसद भवन के चारों तरफ 144 धारा लागू कर दी जाती है, एक कटघरा खड़ा कर दिया जाता है 144 धारा का। अगर कोई घटना हो, कोई विशेष बात हो, तो दफा 144 का लगाया जाना समझ में आ सकता है, लेकिन हमेशा के लिए 144 धारा को लगाना मैं उचित नहीं समझता हूं क्योंकि आप इसके द्वारा किसी भी व्यक्ति को यहां संसद में अपनी बात कहने के लिए मना करते हैं और इस तरह से उसके ऊपर पाबन्दी लगा देते हैं। अगर आप इसको स्थायी रूप से लगाये रखेंगे तो वह टूटेगी और उसकी इज्जत भी नहीं होगी। अगर कोई विशेष कारण समझकर आप धारा 144 लगाते हैं तो वह बात समझ में आ सकती है। लेकिन स्थायी तौर पर धारा 144 को लागू करने की जो पद्धति है, वह मुझे उचित मालूम नहीं देती है।

श्री विद्या चरण शुक्ल : जहां तक डाक्यूमेंट हिन्दी में देने का सवाल है, इसमें चार डाक्यूमेंट की जरूरत होती है। इसमें तीन तो शुरू से ही हिन्दी में थे। फर्स्ट इन्फारमेशन तो हिन्दी में दी गई, रिकवरी मीमो भी हिन्दी में दिया गया और साइट प्लान इत्यादि भी हिन्दी में दिये गये थे। केवल एक 'कम्पलेंट' ही अंग्रेजी में दी गई थी।

जहां तक कानूनी प्रावधान का सवाल है, काननी प्रावधान अंग्रेजी में भी दिये जा सकते हैं और यदि अभियुक्त अंग्रेजी न समझे तो हिन्दी या उर्दू में दिये जाते हैं। जब उनसे इस बारे में कहा गया कि वे कम्पलेंट पर दस्तखत करें, तो उन्होंने कहा कि जब तक हमें हिन्दी में कम्पलेंट नहीं दी जायगी तब तक हम दस्तखत नहीं करेंगे तो उसको भी हिंदी में दिया गया। तीन चीजें हिन्दी में थीं और केवल एक चीज़ अंग्रेजी में थी।

जहां तक अदालत के व्यवहार का सवाल है, मैं यह नहीं कहता कि वह व्यवहार कहां तक उचित था या अनुचित था, लेकिन मैं यह जरूर कहूंगा कि वह व्यवहार किसी तरह से डिसक्रिमिनेटिंग नहीं था चाहे वह कांग्रेसवालों के साथ हो या गैर-कांग्रेस वालों के साथ हो। अभी कुछ दिन पहले मेट्रोपोलिटन कौन्सिल के कुछ कांग्रेसी सदस्य और इसी माननीय सभा के एक कांग्रेसी सदस्य ने इसी तरह का व्यवहार किया था तो उनके ऊपर भी मुकदमा चला था और सजा हुई थी। उनके साथ भी इसी तरह का व्यवहार किया गया था। ऐसा नहीं कि उनको कुर्सी दी गई। इन लोगों को भी कुर्सी दी गई या नहीं दी गई, जो यह कार्यवाही हुई वह उचित हुई या अनुचित हुई, मैं इस बारे में कुछ नहीं कहता। लेकिन मैं यह जरूर कहूंगा कि यह कार्यवाही किसी तरह से डिसक्रिमिनेटरी नहीं थी।

जहां तक धारा 144 का सवाल है और उसको संसद के चारों तरफ लगाने से संबंध है, इस संबंध में जिला मेजिस्ट्रेट अपने डिसक्रिशन का उपयोग करते हैं। उनको जिस तरह की सूचना मिलती है और जैसा

वह आवश्यक समझते हैं, उसके मुताबिक वह कार्यवाही करते हैं और हम इस पर हस्तक्षेप नहीं करते है ।

THE DEPUTY CHAIRMAN : Mr. B. K. P. Sinha. Please be very brief.

SHRI P. N. SAPRU (Uttar Pradesh) : Madam, I want to say something.

THE DEPUTY CHAIRMAN : I will call you after Mr. Sinha.

SHRI B. K. P. SINHA (Bihar) : Madam, I am surprised that this issue is being treated as a pure and simple law and order issue, the issue of violation of law and order and the arrest of the Ministers. But let me repeat what I said yesterday, that this is an unprecedented step that has been taken. May be, the situation was unprecedented; therefore the action was unprecedented in free India. I know about Sheikh Abdulla it was only when the order of dismissal had been served on him that he was arrested. Let me inform the hon. Minister that the order of arrest reached the authorities at Gulmarg but the order of dismissal did not. There was a telephonic talk between Srinagar and Delhi, and Delhi said, so long as the order of dismissal was not served on him, he could not be, and should not be, arrested. And then a special messenger ran to Srinagar by car. The Sadar-I-Riyasat issued the order of dismissal. One minute after the order of dismissal was served and only thereafter, the next moment, was the order of arrest served. Now this raises very grave constitutional issues. They continue to be Ministers of the U.P. Government and they are in jail here.

AN HON. MEMBER : They are sending orders from the jail.

SHRI B. K. P. SINHA : Yes, they are sending orders from the jail. They have called their Personal Assistants, Private Secretaries and dictated orders to them.

श्री विमलकुमार मन्नालालजी चोरड़िया (मध्य प्रदेश) : उनको भी जेल हो गई ।

SHRI B. K. P. SINHA : Do the Government realise that this action of the Government, may be it is hundred per cent. justified, has led to a constitutional stalemate of an unprecedented character? May I know, Madam, if the Government of India are applying their minds to this aspect of the problem? I hope they will excuse me, because it is my feeling—the Treasury Benches will excuse me—if I say that this country is only in a formal sense being run by politicians. Actually it is being run by civil servants who are driving them to all sorts of wrong action. Therefore, I would specially like the Leader of the House to convey to the Prime Minister, the Home Minister and the Deputy Prime Minister whether they have considered this aspect of the matter.

SHRI ABID ALI (Maharashtra) : It is not the feeling of the House. Only some individual Members have that feeling.

(*Some Hon. Members stood up in their seats.*)

THE DEPUTY CHAIRMAN : I am calling one by one.

SHRI B. K. P. SINHA : I speak for myself. I do not speak for Mr. Abid Ali and I cannot speak for him because God made us differently we cannot be one. We cannot be the same.

SHRI BHUPESH GUPTA (West Bengal) : You mean Mr. Abid Ali was made by God. That is why he has been behaving wrongly.

SHRI B. K. P. SINHA : My next question, Madam, is that if the reports are correct—and the Minister's report is correct—12 people were participating. If the politicians had impressed on the officers some tact, some amount of reasonableness, it was easy to put the other ten into police vans and take them away and tell these two gentlemen, "Now you collect fifty more flags and go shouting to the Parliament House". If that sort of step had been taken, this Constitutional stalemate could have been avoided.

Secondly, if policemen could have put them in cars—they could have put them in DLZ cars;—and if they have not one, they could be hired from the Taxi Services—respectfully and driven them to Lucknow and released them there.

SHRI VIDYA CHARAN SHUKLA : Madam, I would invite the attention of the hon. Member to section 197 of the Criminal Procedure Code...

SHRI BHUPESH GUPTA : That we know.

SHRI VIDYA CHARAN SHUKLA : ... which provides that :—

"Any public servant who is not removed from his office, save by or with the consent of a State Government, or of the Central Government ... any offence alleged to have been committed by him while acting or purporting to act in the discharge of the official duty, no court, shall take cognizance of the offence, etc. etc..."

Now, Madam, here it is not a case where the accused were acting in the discharge of their official duty. They were ordinary citizens, and I do not think anybody can support this view... (*Interruption*)—I may be allowed to complete my answer—that a particular person who commits an alleged offence should be differently treated by the law or the law enforcement authorities than another citizen who is alleged to be committing the same offence irrespective of the position one may occupy in his life, and, as has been suggested by the hon. Members that others could have been arrested for committing the same offence but the Ministers could have been let off, and they could have been arrested or should not have been arrested for committing this offence. We had thought about this whole matter and we came to the conclusion that equality before law should be maintained at all costs.

Another point that the hon. Member raised was regarding the powers of civil servants. I want to repudiate that suggestion and that accusation with all the emphasis a my command. There is no question and it is not a fact. Anybody who knows the working of the Government of India at close quarters would not be able to say a think like that.

SHRI P. N. SAPRU : What I wanted to say has been said very ably by my friend, Mr. B. K. P. Sinha. I think it is a very serious matter and it is a matter which should not be looked at from a narrow, legalistic point of view. May be it is right from a formal, legalistic point of view. Madam, it is a question which raises a question of relationship between the Centre and the States. The Ministers have got a right to be treated with some respect and dignity. I would like to know how my friend, Mr. Shukla, and Mr. Abid Ali, feel if they went to Uttar Pradesh and ...

SHRI ABID ALI : Defied the law.

SHRI P. N. SAPRU : ... defied the law. It smacks of a lack of common sense on the part of Mr. Shukla to deal with thing of this magnitude like this.

SHRI VIDYA CHARAN SHUKLA : Madam, as far as this question of respect and dignity is concerned, I agree with the hon. Member that the State Ministers are definitely entitled to get all the respect and dignity that we are capable of giving. There is no dispute about that. But the real question is of violatioin of law. When anybody violates a law, whether he is a Minister or not a Minister, action has to be taken against *him in accordance with the provisions* of law. The question of common sense does not arise here.

As far as the question of State and Centre relationship is concerned, I am afraid we are dealing with these matters strictly from the point of law. The question of relationship does not arise here.

SHRI BHUPESH GUPTA : Madam, listening to the hon. Minister in the Ministry of Home Affairs, I had the feeling that I was listening to a police constable and not a member of the Government.

SHRI A. P. CHATTERJEE (West Bengal) : An illiterate one.

SHRI BHUPESH GUPTA : Yes, an illiterate Head Constable. Madam, I hope the House will be forced to think about the political, Constitutional implications of what they have done. The problem cannot be brushed away much less disposed of by the kind of answer given just now. First of all, it is an unprecedented thing. Here is a Federal Government functioning in the name of the Constitution arresting two Ministers of a constituent unit of the Indian Union. Well, they come here with all the knowledge of law and other things. They came here to make certain representations with regard to the Hindi language on which the Government, again, the Government of which they are a part, namely, the U. P. Government, had taken a clear stand. And it should be presumed that they came here in pursuance of the stand of the Uttar Pradesh Government according to the Constitution and in terms of our Constitution. This is number one.

Secondly, they should have taken into account the fact that there is a political situation in the country centring round the question of language. Therefore, the problem should have been tackled politically I should like to know whether the Prime Minister and the Home Minister were consulted and action was taken on specific instructions from them I say this thing because in a comparable situation in West Bengal when important political leaders of one party were arrested, the arrests took place after getting prior consent of the Chief Minister concerned Dr B C Roy, I know had to do this on many occasions. I should, therefore, like to know whether the Prime Minister and the Home Minister were told by these authorities "Now we are faced with a situation when we think we have to arrest two Ministers What is your opinion?" I should like to have a specific answer to that No general things Then, Madam, in section 144 Cr P C where does it give a mandate to the Government that arrests must take place? We had violated section 144, many of us here on this side and on that side Can anybody say every time he was arrested? It is discretionary and it is for the Magistrates and others concerned to decide, taking into account the situation prevailing, whether actually the arrest should be effected In our days, in the 'thirties' we went to defy section 144 and we violated it But sometimes the police did not arrest us because the Government instruction to them was "Let them defy" So long as violent incidents do not take place, so long as there is no breach of peace, there is every reason for the Government to exercise restraint even in an ordinary situation Here was a political situation, and the Government acted with the mentality of a Havildar and that is what I object to What was the need for arresting them, I should like to know Madam, he said that under the law, the arrest must take place Where does the law say so? Well, about section 144—layers are here and Mr Arun Prakash Chatterjee and other, I hope, will explain the position—does not give a mandatory direction under our Constitution or even under the Criminal Procedure Code or other relevant laws that you have no other alternative but to effect the arrest immediately

THE DEPUTY CHAIRMAN Please wind up Others also have to speak

SHRI BHUPESH GUPTA : Let me finish Don't cut my threads of argument Therefore, I say that here the Minister is displaying his colossal ignorance which can be matched only by his arrogance Therefore, I say that Government acted in this matter with a view to provoking people and with a view to estranging the Centre State relations thereby creating an *alibi* for doing other things Madam Deputy Chairman, we cannot take with equanimity what they have done Two Ministers came here Why did the Prime Minister not go to meet them? Why didn't the Home Minister go to meet them? I have seen that sometimes when processions came near the Bengal Assembly in Calcutta, even the Chief Minister went to meet them, called the leaders and talked to them Nothing of that kind was done here The Begum was in her seat, in authority of power and the Moghul Jawan sat in his seat never caring for what was going to happen I say this is a mentality of Facists, this is a mentality of political arrogance, this is a mentality of people who have lost all their commonsense and sense of public decency (*Interruption*) mentality of the decrepit and morally reprehensible creatures who are at the top of public life (*Interruption*) Madam, I am not raising any legal question I can only express my feeling of anguish and abhorrence at what they have done. They have defied our Constitution They have defamed the country before the world. They have shown that our federal system is such where in the Capital of India, under the very nose of the President and the Prime Minister, two Ministers of a State, sworn under oath of office, can be arrested, insulted and humiliated and not even given a chair As a boy, I received a chair in the British court But they were not given chairs Have we run short of chairs here? The Ministers' houses are furnished here to the extent of Rs 40,000 Can't you produce more chairs in the court? Anyhow, a chair could be brought Madam Deputy Chairman, political vendetta, political revenge malice and monstrosity have been exhibited by this Government To call it a Government is to shame the name of Government I say—I do not know what to say against these people

THE DEPUTY CHAIRMAN . Then don't say

SHRI ABID ALI Go to Russia.

(*Interruption*)

SHRI BHUPESH GUPTA · No, Madam, I want to say, you help me. Where is the Prime Minister? Where is

[Shri Bhupesh Gupta.]

the Home Minister?—I should like to know. They have sent an underlining of a Home Minister to give an answer. Well, this is how we feel. I say that we should condemn that action of the Government.

(*Interruption*)

THE DEPUTY CHAIRMAN : Order, please. When a statement is made, I need not even allow clarifications. That is the rule of procedure. But having been allowed to put questions in the form of seeking clarifications, one should not just make statements, for there is nothing for the Minister to answer in the type of statement that has just been made. Therefore, I would request Members to please ask for clarifications. I am willing to give another ten minutes. Mr. Chatterjee.

SHRI VIDYA CHARAN SHUKLA : Madam, I have to say something about what Mr. Bhupesh Gupta said. Madam, I do not want to indulge in indecent hysteria like his and reply to him in the same manner he has done. (*Interruption*) I do not want to indulge in vulgar charges . . .

SHRI BHUPESH GUPTA : What is vulgar ?

SHRI VIDYA CHARAN SHUKLA : Your charges that have been made against me personally such as 'illeterate Head Constable' and things like that. I cannot decend down to that level.

SHRI BHUPESH GUPTA : On a point of personal explanation. I said I had a feeling like that.

(*Interruption*)

SHRI VIDYA CHARAN SHUKLA : I am not accustomed to vulgarity and that is why I would not go into all that. I would limit myself to whatever points he has made here. Now he has asked whether the Prime Minister or the Home Minister was consulted before effecting this arrest. I would like to say that no such consultation took place. The only instruction that was given to the Delhi Administration was that nobody, irrespect of status, should be allowed to break that law in the Union Territory of Delhi. As far as the second question is concerned, about what will happen in a Central Minister went to U.P. or other States and got arrested, I would say that if any Minister, whether of the Centre or of a State Government, defied any law anywhere, I should think that the authority should proceed according to law in dealing with them. I would not mind that. As far as the charge of political vendetta is concerned, I emphatically repudiate that. There is no question of political vendetta in this matter.

SHRI A. P. CHATTERJEE : Madam Deputy Chairman, the Minister was purely legal in his expositions. Now I will put some questions to him. Does he know or does he not know that violation of section 144 is a non-cognizable offence and, therefore, the police cannot arrest without a warrant from a Magistrate? Secondly, were these two Ministers arrested with a warrant from the Magistrate? Thirdly, if not, under what authority, the two Ministers of the State of U.P. were arrested? Fourthly, what violation of the order under section 144 was really committed by these Ministers? The order under section 144 might have stated that an unlawful assembly of five or more persons is prohibited. Will the hon. Minister enlighten the House whether along with these two Ministers, others also were arrested? Is it the contention of this Government that these two Ministers formed an unlawful assembly with some other persons? If so, who are those other persons? Then the next question I would like to ask is that Mr. Chandra Shekhar has surprisingly said that chairs are not allowed to be placed for the accused. . .

SHRI CHANDRA SHEKHAR : I did not say that.

(*Interruption*)

SHRI A. P. CHATTERJEE : Madam, he spoke in Hindi and I am very much ignorant of Hindi and so I could not follow. So these are the questions which I would like the hon. Minister to answer. I would like to mention another thing also. This is a very serious Constitutional question. India is a Union of States. That is the first Article of our Constitution. If it is not strictly federal, it is at least a quasi-federal State. Ministers of States which constitute the Union should be given proper respect and proper honour. What authority has the Federal Government got to arrest a Minister of a State which is a constituent of this Union? These are the questions to which I would like the Minister to give answers.

SHRI VIDYA CHARAN SHUKLA : I have already stated that the Ministers of the State are perfectly entitled to get all the respect and consideration from

the Government. There is no dispute about it. But I do not think this is anybody's case that they should have the liberty of breaking the law also. This is nobody's case. As far as the other legal points which the hon. Member has raised are concerned, I would say that this case is under trial by a court and these matters are being discussed there. Therefore I would not comment on them.

श्री गंगा शरण सिंह (बिहार) : मैडम, अभी कुछ देर हुई कि हमारे मिनिस्टर साहब ने यह बतलाया कि अभियुक्तों को अदालत में कुर्सी देने का रिवाज नहीं है, नियम नहीं है, तो मैं यह जानना चाहता हूं कि यह नियम कब से बना, किसने बनाया। क्या अंग्रेजों के जाने के बाद ब्रिटिश राज के खत्म होने के बाद, यह नियम बनाया गया। क्योंकि मुझे मालूम है और कई दर्जन आदमी इस हाउस में भी होंगे जो कि बतायेंगे कि अंग्रेजी राज के जमाने में जब हम कचहरी में अभियुक्त की हैसियत से गये तो हम लोगों को कुर्सी मिली, तो क्या अंग्रेजों के जाने के बाद से यह तब्दीली की गई और किसने यह नियम बनाया, कब बनाया। मिनिस्टर को जब कुछ ऐसी बातें करनी चाहिये तो पूरी जिम्मेदारी के साथ और समझ कर करनी चाहिये। वह समझते नहीं हैं कि उनके इस कहने पर दूसरी जगहों में, सारी स्टेटों में, सारे मुल्क में, क्या असर होगा। यह परम्परा कब से चली, किसने चलाई कि अभियुक्त को कुर्सी नहीं दी जा सकती है। मेरा ख्याल है, हालांकि बहुत से नये लोग आ गये हैं लेकिन फिर भी दर्जनों ऐसे आदमी अभी भी यहां मौजूद हैं जो कि राष्ट्रीय आंदोलन के जमाने के हैं जो कि बतला सकते हैं कि पहले जमाने में जब कि अंग्रेजों से हम लड़ाई लड़ रहे थे, उनके कानूनों का उल्लंघन कर रहे थे उस समय हमें कुर्सियां दी जा रही थीं, अभियुक्त की हैसियत से। यह नया तरीका, नया सिद्धांत, नई परम्परा शुक्ल जी ने कब से निकाली ?

श्री विद्या चरण शुक्ल : मैडेम, मैं इसका जवाब दे दूं। मैं इसका जवाब यह देना चाहता हूं कि जहां तक कुर्सी देने के औचित्य या अनौचित्य का सवाल है मैंने कुछ नहीं कहा, मैं व्यक्तिगत रूप से यह मानता हूं कि कुर्सी देनी चाहिये। कुर्सी देना उचित है या अनुचित इस के बारे में मैंने कुछ नहीं कहा लेकिन जिस तरह की आज यहां पर परम्परा चल रही है, दिल्ली में, उसके बारे में मैंने कहा कि इस तरह की परम्परा यहां चल रही है।

श्री गंगा शरण सिंह : कब से चली, किसने चलाई ?

श्री विद्या चरण शुक्ल : यह मुझे इस वक्त मालूम नहीं कि कब से चली है। परन्तु मैंने यह नहीं कहा कि यह उचित है या अनुचित है, इसके बारे में मैंने जरा भी नहीं कहा।

SHRI TRILOKI SINGH (Uttar Pradesh) : Madam, apprehension of breach of peace, whether it exists or not, is the discretion of the Magistrate and not of the Government. The person who defies the law, whether he should be arrested or not, that also is the discretion of the Magistrate or the police officer and not of the Government. My question arises out of the answers given by the hon. Minister. He said that instructions had been issued by the Government that in case of defiance the law should be strictly enforced. May I know under what section of the Criminal Procedure Code or the I.P.C. or under what standing practice or power the Government issued instructions to the police authorities and the magistracy at Delhi to enforce section 144 strictly. That is one question. The other thing is that the Minister has admitted that the Government and the magistracy at Delhi and the police also had previous information that these two Ministers were coming to Delhi to defy the order under section 144. It is also well known, and perhaps the Minister knew that before such defiance they had seen the Speaker of the Lok Sabha and the Deputy Chairman of the Rajya Sabha and had also sent some communication to the Prime Minister and also to the President. With all this previous knowledge,

[Shri Triloki Singh.]

may I know whether the police, which arrested these gentlemen for defiance of section 144, should not have taken due care and precaution, as was taken in the days of slavery when Pandit Madan Mohan Malaviya defied section 144, when C. R. Das defied section 144, when Pandit Motilal Nehru defied section 144 and that necessary arrangements for their transport to the Jail, for all their conveniences and comforts were taken? Why was it not done? I would like the Minister to answer these questions.

SHRI VIDYA CHARAN SHUKLA: Madam, as far as the question of instructions is concerned, there was no question of issuing instructions specifically to meet this particular situation. The question is, that law and order matters are the direct responsibility of the Union Home Ministry. Our general instructions to the Delhi Administration are that the laws in force must be strictly implemented and enforced. As far as the question of necessary arrangements for their comfort and transport is concerned, all the arrangements were made for their comfortable transport and other comforts. There is no complaint of any discomfort from these arrested gentlemen.

श्री राजनारायण : माननीया, मैं तीन सवाल इस बारे में पूछ रहा हूं श्री चन्द्र शेखर जी ने जो बात की उसके लिये बता दूं कि सरकार को और चन्द्र शेखर जी को यह बात मालूम होनी चाहिये कि 4 दिसम्बर को वाराणसी में 144 थी और करीब 25 हजार का जलूस ले कर—कुछ अखबार वालों ने 20 हजार दिया, कुछ ने 15 हजार दिया लेकिन 25 हजार करीब विद्यार्थियों का जलूस ले कर—मैं चला और 144 थी लेकिन कही हमारी गिरफ्तारी नही हुई और साढे सात बजे डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट ने यह कहा कि चूंकि इतना बड़ा प्रोमेशन शान्तिपूर्ण तरीके से निकला और शान्तिपूर्ण तरीके से हुई और लोगों ने खुद अंग्रेजी के साइनबोर्ड हटा लिये इसलिये 144 दफा की आवश्यकता नहीं है।

श्री चंद्र शेखर : वह तो आप यहां भी नही पकड़े गये।

श्री राजनारायण : माननीया, देखिये, वह इस चीज़ को हंसी में मत उड़ायें, जब गम्भीर सवाल हो तो गम्भीरता से सोचना चाहिये।

भूपेश गुप्ता जी ने बहुत सही बात उठाई है कि संविधान में, कानून में नियम मे, उपनियम में कहीं यह नही लिखा है कि दफा 144 तोड़ी जाय तो गिरफ्तारी झखमारे कर होगी ही। तो यहां की मजिस्ट्रेसी ने और पुलिस अधिकारियो ने जो बात की है उसके बारे मे सरकार क्या सोच रही है?

दूसरी बात यह कि मंत्री जी ने कहा कि देरी क्यों हुई लेकिन मेरी अपनी जानकारी है, मै नाम नहीं बताऊंगा, मुझे बताया गया, कि ढाई घंटे की देरी इसलिये हुई कि अपराध बनता ही नही था। हमको मालूम हुआ है, पुलिस अफसरों ने अपने लीगल सलाहकारों से सलाह ली, कोई साढ़े दस या ग्यारह बजे हमें सरकारी अफसरों से जानकारी हुई कि अपराध बनता ही नहीं था इस लिये अपराध कैसे बने उस ढंग से ही कम्प्लेट तैयार करने में इतनी देरी हुई। तो सरकार इसको जाने और जान कर के इस पर उचित कार्यवाही करे।

और तीसरी बात जेल की है। आज मै जेल में गया। श्री प्रभुनारायण सिंह तो श्रम मंत्री है और श्री रामस्वरुप वर्मा वित्त मंत्री है और वहा इनका इम्पार्टेन्ट विधेयक लेबर रिलेशंस का आ रहा है जो 18 दिसम्बर से उत्तर प्रदेश की विधान सभा चल रही है उसमें और सप्लीमेंटरी बजट वित्त मंत्री को 18 तारीख को पेश करना है तो वह चाहते है कि उनके सेक्रेटरीज जो है, उनके टाइपिस्ट्स जो है, और उनको और जितनी ज़रुरते हों, वे सब बाकायदा जेल में उनको सुलभ हों। तो क्या सरकार यह आदेश जेल अधिकारियों को देने जा

रही है कि इनको पूरी सहूलियतें मिलें क्योंकि वे अब मिनिस्टर है और उन्हें अपने कर्तव्यों का निर्वाह करना है ।

श्री विद्याचरण शुक्ल : उपसभापति महोदया, जहां तक यह है कि दफा 144 बनारस में थी और उसकी इनके ऊपर कार्यवाही नही की गई तो इसका जवाब मे नही दे सकता, उत्तर प्रदेश की सरकार ही जवाब दे सकती है कि क्यों कार्यवाही नही की गई या क्यों कार्यवाही करनी है, इसका मैं उत्तर नही दे सकता । जहां तक शांतिपूर्ण जलूस निकालने का सवाल है तो यह बड़ी अच्छी बात है कि जलूस शान्तिपूर्ण ढग से निकला ।

श्री राजनारायण : यहां भी था ।

श्री विद्या चरण शुक्ल : जहा तक देरी होने का सवाल है तो पेपर्स तैयार होने मे जितना समय लगा उतना ही समय लगा, उसमें कोई देरी नही हुई ।

जहां तक जेल मे सुविधायें देने का सवाल है, नियमानुसार जो भी सुविधाये दी जा सकती है वे अवश्य दी जायेंगी ।

श्री राजनारायण : यह नियम के अनुसार है या नही ।

(*Some hon. Members rose to ask questions*)

THE DEPUTY CHAIRMAN : I am going to the regular business. No more questions on this. Miss Shanta Vasisht on the Motion regarding C.I.A.

MOTIONS *RE* ESPIONAGE ACTIVITIES IN THE COUNTRY—*contd.*

THE DEPUTY CHAIRMAN : I would like the House to sit through the Lunch Hour if more Members must participate in the debate on the two motions that are before the House. We must finish this before 2-30 or 3-00. Kumari Shanta Vasisht.

SHRI HARISH CHANDRA MATHUR (Rajasthan) : Madam, when is the Home Minister likely to be called ?

THE DEPUTY CHAIRMAN : At about 3 O'clock.

SHRI BHUPESH GUPTA (West Bengal) : Are we doing it just to adjust the Home Minister ?

THE DEPUTY CHAIRMAN : No.

SHRI BHUPESH GUPTA : The Home Minister will come when we finish it.

THE DEPUTY CHAIRMAN : Kumari Shanta Vasisht. I would request all Members to restrict themselves to ten minutes each only. Otherwise, it will not be possible for many Members to speak.

KUMARI SHANTA VASISHT (Delhi) : Madam Deputy Chairman, this question of the activities of the CIA has come up and has been debated since yesterday and it has brought into focus many doubts and questions that were agitating the minds of the people of India, and I think that any Government has to look upon these matters very seriously and to see how far these activities are interfering in the internal affairs of this country.

If you recall, Madam, some months back I had referred in one of my speeches that there was a lot of interference in the last General Elections. I had also referred to the foreign money in the Kerala elections some many many years back when the communist Ministry was thrown out, the very first communist Ministry was thrown out, and I had referred after that—it must be about six years back or so when I had said that some foreign money had come, which had played a part and had influenced the politics of the Kerala Government at that time when the question was as to how to sort of thwart the ways of that communist Government. And even recently I had pointed out the role of foreign money in this country. I think, Madam, we are not concerned so much with what Mr. Smith has said, how far his statement is true or not is not the question, but the question is whether this is true, as to how far espionage activities are going on in our country and to what extent they are interfering in the administration of our country, and otherwise, in our internal affairs, and which all countries are participating in such activities and to what extent, and how far it colours the complexion of